सांध्य दैनिक

4PM

जिद...सच की

www.4pm.co.in www.facebook.com/4pmnewsnetwork @Editor_Sanjay YouTube @4pm NEWS NETWORK

● वर्ष: 10 ● अंक: 41 ● पृष्ठ: 8 ● लखनऊ, बुधवार, 13 मार्च, 2024

मूल्य ₹ 3/-

बड़ा वेतन और छोटी जिम्मेदारी शायद ही कभी एक साथ पाए जाते हैं।
-नेपोलियन हिल

टी-20 वर्ल्डकप से बाहर हो सकते... 7 | सीएए का नोटिफिकेशन या चुनावों... 3 | क्या हेगड़े पर कार्रवाई करेंगे... 2

इलेक्टोरल बॉण्ड के सहारे विपक्ष के निशाने पर आई मोदी सरकार

कांग्रेस का प्रहार- किस बात से डरे हुए हैं प्रधानमंत्री

» एसबीआई ने सूची चुनाव आयोग को सौंपी

» सीजेआई के आदेश को रोकने की मांग

4पीएम न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली। एसबीआई ने इलेक्टोल बॉण्ड पर अपनी सूची निर्वाचन आयोग को सौंप दी है। साथ ही उसने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दे दिया है कि उसने पासवर्ड के साथ पूरी सूची को पेन ड्राइव में चुनाव अयोग को दे दिया है। इन सबके बीच सियासी हंगामा भी मच गया है। कांग्रेस ने इस बाबत केंद्र की मोदी सरकार व बीजेपी को घेर लिया। वहीं मुख्य न्यायाधीश के आदेश को रोकने की मांग राष्ट्रपति से की गई है।

गौरतलब हो फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को अवैध करार देते हुए उस पर रोक लगा दी थी। साथ ही एसबीआई को कहा था कि एसबीआई को अब तक खरीदे गए बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को दी जाए।

राष्ट्रपति के दफ्तर में पहुंची चिट्ठी

ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदिश सी अग्रवाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर आग्रह किया कि वे चुनावी बांड योजना मामले में फैसले का राष्ट्रपति संदर्भ लें और इसे प्रभावी न करें। अग्रवाल ने राष्ट्रपति को लिखे अपने पत्र में कहा कि विभिन्न राजनीतिक दलों को योगदान देने वाले कॉरपोरेट्स के नामों का खुलासा करने से गंभीर असर पड़ सकता है। इसमें प्रेसिडेंसिशियल रेफरेंस का जिक्र कर रोक की मांग की गई है।

एसबीआई के माध्यम से अड़ंगा लगा रही सरकार : जयराम

कांग्रेस ने बुधवार को आरोप लगाया कि सरकार भारतीय स्टेट बैंक(एसबीआई) के माध्यम से लगातार इस बात को सामने आने से रोकने या देरी करने की कोशिश कर रही है कि किसने, किस राजनीतिक दल को कितना चंदा दिया। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह सवाल भी किया कि आखिर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी किस बात से डरे हुए हैं? रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया, ''15 फरवरी 2024 को चुनावी बॉण्ड को असंवैधानिक घोषित करने वाले उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद से मोदी सरकार एसबीआई के माध्यम से लगातार इस बात को सामने आने से रोकने या देरी करने की कोशिश कर रही है कि किसने, किस राजनीतिक दल को कितना चंदा दिया। उन्होंने सवाल किया, ''प्रधानमंत्री किस बात से इतने डरे हुए हैं?चुनावी बॉण्ड के आंकड़ों से कौन सा नया घोटाला सामने आएगा?'' रमेश ने दावा किया कि 20 फरवरी 2024 को पता चला था कि ईडी, सीबीआई या आयकर विभाग के छापे या जांच के तुरंत बाद 30 कंपनियों से भाजपा को 335 करोड़ रुपए तक का चंदा मिला है।

बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति ने खुद को किया अलग

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति ने एससीबीए प्रमुख आदीश सी अग्रवाल द्वारा लिखे गए पत्र से खुद को अलग कर लिया, जिसमें चुनावी बांड योजना मामले में शीर्ष अदालत के फैसले के राष्ट्रपति के संदर्भ की मांग की गई थी। बार एसोसिएशन ने भी पत्र की सामग्री की निंदा की, इसे सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार को खत्म करने और कमजोर करने का प्रयास बताया।

15 मार्च तक चुनावी बांड का विवरण प्रकाशित करने के भी आदेश

सुप्रीम कोर्ट की फटकार के एक दिन बाद एसबीआई ने चुनाव आयोग को चुनावी बांड का डेटा सौंपा। सुप्रीम कोर्ट ने पोल पैनल को 15 मार्च को शाम 5 बजे तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर चुनावी बांड का विवरण प्रकाशित करने का भी निर्देश दिया है।

सीईसी-ईसी की नियुक्ति मामले में सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट सहमत

» 15 मार्च को होगी बहस कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने दाखिल की थी याचिका

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के खिलाफ दाखिल की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 15 मार्च को सुनवाई करेगा।बता दें कि कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ती के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

उन्होंने अपनी याचिका में सीईसी अधिनियम, 2023 के प्रावधानों को चुनौती दी थी। याचिका में उन्होंने सीईसी अधिनियम, 2023 की धारा 7 और 8 के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग की है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार नियुक्ति की मांग

इसके साथ ही कांग्रेस नेता जया ठाकुर की ओर से दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है। जिसमें सीईसी-ईसी की नियुक्ति के लिए सीजेआई, प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता की एक समिति के गठन का निर्देश दिया गया था।

भाजपा कर रही 'वोट बैंक की गंदी राजनीति' : केजरीवाल

» पड़ोसी देशों को रुपये बांटना चाहती है सरकार

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता (संशोधन) अधिनियम को लागू करना भाजपा की ''वोट बैंक की गंदी राजनीति है। उन्होंने कहा कि लोग चाहते हैं कि इस कानून को निरस्त किया जाए। केजरीवाल ने कहा कि इस कानून के जरिए केंद्र की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार ने पाकिस्तान और बांग्लादेश से बड़ी संख्या में गरीब अल्पसंख्यकों के भारत आने के द्वार खोल दिए हैं। उधर भाजपा ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विपक्ष राजनीति कर रही है और माहौल खराब करना चाहता है॥

आप के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में 3.5 करोड़ अल्पसंख्यक हैं। भाजपा हमारे लोगों का पैसा पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए गरीब प्रवासियों को यहां नौकरी और घर देकर बसाने में खर्च करना चाहती है। आने वाले चुनावों में भाजपा को फायदा होगा क्योंकि पड़ोसी देशों से भारत में बसने वाले गरीब अल्पसंख्यक उसके वोट बैंक बन जाएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले सीएए लागू करना भाजपा की वोट बैंक की गंदी राजनीति है। देश सीएए को निरस्त करने की मांग करता है। अगर कानून रद्द नहीं किया गया तो वे भाजपा के खिलाफ वोट करें।

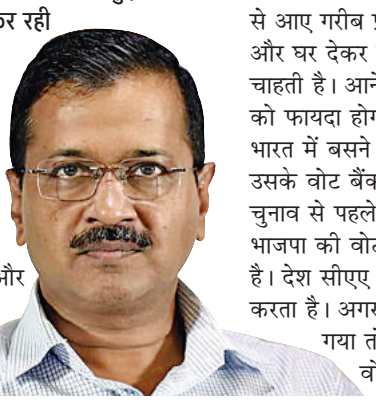

क्या हेगड़े पर कार्रवाई करेंगे पीएम : जयराम

» भाजपा का इरादा संविधान बदलने का : उदित राज

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया, प्रधानमंत्री अपने राजनीतिक लाभ के लिए महात्मा को लेकर ओछी-ओछी बातें करते हैं, लेकिन क्या वह महात्मा गांधी के अहिंसा, सबको साथ लेकर चलने और समानता के आदर्शों के प्रति प्रतिबद्ध होंगे? उन्होंने सवाल किया, प्रधानमंत्री ने संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखने की शपथ ली थी। क्या वह संविधान के प्रति अपनी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता दिखाने के लिए कर्नाटक से भाजपा सांसद अनंत कुमार हेगड़े के खिलाफ कार्वाई करेंगे? कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हेगड़े के बयान के खिलाफ प्रदर्शन किया।

पार्टी नेता उदित राज ने आरोप लगाया कि भाजपा का इरादा संविधान बदलने का है और हेगड़े का बयान इसी का संकेत है। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनंत कुमार हेगड़े के एक बयान को लेकर कहा कि क्या प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी संविधान के प्रति अपनी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता की खातिर हेगड़े के खिलाफ कार्वाई करेंगे। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद हेगड़े ने रविवार को कहा था कि संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाने के लिए भाजपा संविधान में संशोधन करेगी। उन्होंने लोगों से लोकसभा में भाजपा को दो-तिहाई बहुमत देने का आह्वान किया था, ताकि देश के संविधान में संशोधन किया जा सके। भाजपा ने हेगड़े के बयान को उनका निजी विचार करार दिया है।

भाजपा के सत्ता छीनने की कोशिशें सफल नहीं होंगी : सुक्खू

शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य में कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए प्रतिबद्ध है और इसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए कड़े कानून बनाएगी। कांगड़ा जिला और चंबा में जनसभाओं को संबोधित करते हुए सुक्खू ने भाजपा की आलोचना करते हुए कहा कि राज्य में सत्ता छीनने की इसकी कोशिशें सफल नहीं होंगी, क्योंकि लोगों ने कांग्रेस को जनादेश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए प्रतिबद्ध है और यह इसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए कड़े कानून बनाएगी। हालिया राज्यसभा चुनावों में क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के छह बागी विधायकों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने भाजपा पर प्रहार किया और पूछा कि पंचकूला के एक पांच सितारा होटल और उत्तराखंड के ऋषिकेश में महंगे रिजॉर्ट में इनके ठहरने के लिए कौन पैसे दे रहा है। उन्होंने कहा, भाजपा अपने केंद्रीय नेतृत्व की मदद से यह सब कर रही है। लेकिन आखिरकार सच्चाई की जीत होगी और राज्य के लोग खरीद-फरोख्त की राजनीति को कभी माफ नहीं करेंगे। सुक्खू ने कहा, भाजपा ने पैसों का इस्तेमाल कर हमारी सरकार अस्थिर करने की कोशिश की, लेकिन जब तक मैं यहां हूं भ्रष्टाचार के सारे दरवाजे बंद रहेंगे।

झूठी बातें फैला रही है बीजेपी : सिद्धारमैया

चामराजनगर (कर्नाटक)। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के इस आरोप को झूठ बताया कि कावेरी नदी का पानी ऐसे समय तमिलनाडु के लिए छोड़ा जा रहा है जब बेंगलुरु गंभीर जल संकट से जूझ रहा है। सिद्धारमैया ने इसे झूठ करार देते हुए कहा कि तमिलनाडु को पानी की एक बूंद भी नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने यहां पत्रकारों से कहा, यह सब झूठ है। पानी कौन जाने देगा, वह भी इस स्थिति में? हम अपने उपभोग के लिए पानी बचाए बिना तमिलनाडु को पानी की एक बूंद भी नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि न तो तमिलनाडु ने इसके लिए कहा और न ही किसी ने कर्नाटक को पड़ोसी राज्य को पानी छोड़ने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, हम उन्हें (तमिलनाडु को) पानी क्यों देंगे, जब उन्होंने पानी मांगा ही नहीं है? हमारे पास उन्हें देने के लिए पानी कहां है? उन्हें (तमिलनाडु को) पानी देने का कोई सवाल ही नहीं है, भले ही तमिलनाडु या केंद्र सरकार या कोई और हमें पानी छोड़ने का निर्देश दे। नेता प्रतिपक्ष आर. अशोक ने सोमवार को कर्नाटक सरकार पर तमिलनाडु के लिए कावेरी का पानी छोड़ने का आरोप लगाया था। उन्होंने मांग की कि राज्य सरकार तुरंत पड़ोसी राज्य को पानी छोड़ना बंद कर दे और बेंगलुरु के लोगों की दुर्दशा पर ध्यान दे।

रूढ़िवादी अप्रोच वाले नेतृत्व के साथ मैं काम नहीं कर पा रहा था : तेजस्वी

» पिछली सरकार की खोली पोल

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

पटना। महागठबंधन में लोकसभा की सीटों के बंटवारे की चर्चा के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 17 महीने के दौरान किए गए कामों को लेकर वर्तमान राज्य सरकार पर फिर हमला बोला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या अन्य किसी का नाम लिए बिना उन्होंने सरकार को पुराने ख्यालात का बताया है।

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बुधवार को अपने एक्स मीडिया अकाउंट पर लिखा कि गठबंधन धर्म की सीमितता व बाध्यताओं के बीच तथा पुराने ख्यालात, अप्रचलित तौर-तरीके, असामयिक निर्णय, कालग्रस्त कार्यशैली एवं रूढ़िवादी एप्रोच वाले नेतृत्व के साथ मैं अपनी क्षमता का बस थोड़ा ही कार्य कर पा रहा था।

केवल 17 महीनों में ही लाखों नौकरियां दीं

लेकिन इन सब सीमाओं व रुकावटों के बावजूद भी हमने तार्किकता, बुद्धिमत्ता, वैज्ञानिकता और व्यावहारिकता के बल पर केवल 17 महीनों में ही लाखों नौकरियां दी। पर्यटन, आधारभूत संरचना, शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्रों में प्रभावी, बेहतरीन व ऐतिहासिक कार्य किए। आम जनमानस ने 17 साल बनाम 17 महीनों के इस सकारात्मक अंतर को नजदीक से अनुभव कर स्वागत किया।

भाजपा सरकार की एक्सपायरी डेट निकट: अखिलेश

» सपा प्रमुख ने की घूंघट में अस्पताल पहुंची एसडीएम की तारीफ बोले- बीजेपी सरकार से संभलकर रहें अफसर

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। यूपी के स्वास्थ्य व्यवस्था पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल, फिरोजबाद में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला एसडीएम के औचक निरीक्षण के दौरान कई तरह की खामिया पाई गईं, जिसे लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर हमला किया है। सपा अध्यक्ष ने महिला अफसर के साहस की तारीफ करते हुए प्रदेश सरकार पर निशाना साधा।

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव एक्स पर इस घटना का एक वीडियो शेयर किया जिसमें महिला एनडीए कृति राज अस्पताल की निरीक्षण करते दिख रही है. अखिलेश यादव ने कहा, स्वयं घूंघट में जाकर, उप्र की चिकित्सा व्यवस्था पर पड़ा परदा उठाकर सच्चाई दिखानेवाली साहसी महिला अधिकारी को संभलकर रहना होगा। इस डॉक्टर-दवाई के बिना चलनेवाली उप्र की बीमारू चिकित्सा व्यवस्था के गोरखधंधे के खुलासे से शर्मसार हुई भाजपा सरकार कहीं ज्ञानवर्धन के बहाने उनको अध्ययन हेतु विदेश ही न भेज दे। सुना है इस खुलासे के बाद स्वास्थ्य मंत्री जी 'अस्वस्थ-अवस्था' में हैं। रोगी को ठीक करने की जुमांटी (जुमला+गारंटी) देने वाली भाजपा सरकार की भी एक्सपायरी डेट निकट आ गयी है। दरअसल फिरोजाबाद स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों द्वारा कई शिकायतें मिलने के बाद महिला एसडीएम कृति राज खुद ही घूंघट पहनकर अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंच गईं थीं। शुरुआत में तो उन्हें कोई नहीं पहचान पाया, लेकिन जब स्वास्थ्य कर्मियों को पता चला तो हड़कंप मच गया।

प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं चौपट हैं, यूनिवर्सिटी तो बना दी पर विस्तार नहीं हुआ

सपा अध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चौपट हैं। भाजपा सरकार में इलाज नहीं मिलने से लोग तड़प-तड़प कर मरने को मजबूर हैं। अस्पतालों में स्टाफ की कमी के चलते मरीजों को न दवा मिल पा रही है और न ही इलाज हो पा रहा है। अखिलेश ने कहा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत निजी अल्ट्रासाउंड केंद्र गर्भवती की मुफ्त जांच के लिए राजी नहीं है। लखनऊ में करीब 200 निजी केंद्रों पर गर्भवती का अल्ट्रासाउंड होता है। 140 केंद्र सरकार की योजना में शामिल नहीं हैं। उन्होंने कहा कि डॉ. राममनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में चिकित्सा शिक्षकों के 300 पदों, पीजीआई में 1803 पदों और सुपर स्पेशलिटी कैंसर संस्थान में 93 विशेषज्ञ शिक्षकों की भर्ती होनी है।

कांग्रेस में जीतती थी लेकिन भाजपा में हार रही हूं : इमरती

» सिंधिया समर्थक का फिर छलका दर्द

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

ग्वालियर। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए नेता खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं पर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष असहयोग के आरोप लगा रेह हैं। इसकी बानगी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बुलाए गए कार्यकर्ता सम्मेलन में देखने को मिली। सिंधिया समर्थक पूर्व मंत्री इमरती देवी ने मंच से ही अपनी पीड़ा सुनानी शुरू कर दी। उन्होंने यह कहकर सबको चौंका दिया कि जब वे कांग्रेस में थी तो लगातार जीत रही थी। जब से भाजपा में आई हैं, उन्हें हार का सामना करना पड़ रहा है।

दरअसल, भाजपा ने ग्वालियर लोकसभा सीट से अपने वर्तमान सांसद विवेक नारायण शेजवलकर का टिकट काटकर हाल ही में विधानसभा चुनाव हार चुके पूर्व मंत्री भारत सिंह को प्रत्याशी बनाया है। इसके बाद से विधानसभावार पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं। डबरा में ऐसा ही कार्यकर्ता सम्मेलन था, जिसमें सांसद शेजवलकर, प्रत्याशी कुशवाह सहित सभी नेता मौजूद थे। मंच पर पूर्व मंत्री इमरती देवी भी थी। वक्ता भाजपा संगठन और पार्टी कार्यकर्ताओं की निष्ठा को लेकर गुणगान कर रहे थे तभी पूर्व मंत्री इमरती देवी को भाषण के लिए आमंत्रित किया गया। वे आईं तो मन का गुबार मन मे नहीं रोक सकीं।

बामुलाहिजा

कार्टून: हसन जैदी

सीएए का नोटिफिकेशन या चुनावों का ध्रुवीकरण!

» लोस चुनाव से ठीक पहले बीजेपी का सियासी दावं
» विपक्ष ने समय को लेकर उठाया सवाल
» कांग्रेस व सहयोगी बोले- देश को विभाजित करना चाहती है बीजपी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। आखिरकार लोक सभा चुनाव 24 की घोषणा होने से पहले बीजेपी की मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम-सीएए के नाटिफिकेशन को मंजूरी देकर चुनावी दांव चल दिया है। उसके इस फैसले के बाद विपक्ष ने भी भाजपा सरकार पर वोटों के ध्रुवीकरण करने का आरोप लगाया है। सियासी गलियारें में अब चर्चा होने लगी है कि इस दांव का फायदा बीजेपी आगामी चुनाव में मिल सकता है।

वहीं सरकार के इस फैसले पर सवाल भी उठ रहें हैं। भाजपा के विरोधी दलों ने समय को लेकर सरकार की मंशा पर शक करते हुए कहा कि आखिर सरकार ने जब इस कानून को चार साल पहले संसद से पारित करवा लिया था अब तक लटकाए क्यों रखा क्या वह लोक सभा चुनावों का इंतजार कर रही थी। कांग्रेस समेत लगभग सभी दलों ने इसको लेकर विरोध किया है। उधर इसके खिलाफ पूरे देश में धरना प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। भाजपा समर्थक जहां सरकार के इस फैसले पर खुशी जता रहे हैं, वहीं विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ मुखर हो गया है। कांग्रेस ने चुनाव से पहले सीएए लागू करने को बंटवारे की राजनीति करार दिया। वहीं, अब बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पर संदेह जताया है कि यह कानून वैध भी या नहीं।

सांप्रदायिक उद्देश्यों वाला विभाजनकारी कदम : थरूर

केंद्र सरकार की ओर से लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए)-2019 लागू करने की घोषणा के बाद कांग्रेस नेता शशि थरूर ने इसे पूरी तरह से सांप्रदायिक उद्देश्यों के साथ विभाजनकारी और नुकसान पहुंचाने वाला कदम करार दिया। थरूर ने कहा, ''यह मूल सिद्धांत के विपरीत है कि भारत में, आपका धर्म कुछ भी हो, आपकी जाति कुछ भी हो, आपकी कुछ भी हो, आपका रंग कुछ भी हो, आप देश के किसी भी हिस्से में रहते हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप भारत के नागरिक हैं, तो आपके पास अन्य सभी लोगों के समान अधिकार हैं।'' कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) के सदस्य ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि कुछ अधिवक्ता इसे उच्चतम न्यायालय के समक्ष उठाएंगे और इसकी संवैधानिकता को चुनौती देंगे। तिरुवनंतपुरम के सांसद ने सीएए के खिलाफ संसद में पहले कही गई बात को दोहराते हुए कहा कि यह कानून संविधान के मूल सिद्धांत का उल्लंघन है। थरूर ने कहा, ''यह कानून मूल रूप से गलत धारणा वाला है और मेरा मानना है कि यह हमारी सभ्यता की सहस्राब्दी की परंपराओं का भी अपमान है, जहां हमने ईमानदारी से शरण की पेशकश की है।'' कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्होंने खुद केरल में सीएए के खिलाफ सात विरोध प्रदर्शनों की शुरूआत की थी। उन्होंने कहा, ''हम इसके विरोध में खड़े होंगे।'' उन्होंने दावा किया कि भाजपा चुनाव के मद्देनजर सीएए को अधिसूचित करके पूरी तरह से सांप्रदायिक संदेश देने की कोशिश कर रही है।

संशय दूर करने के बाद सीएए को लागू करना बेहतर होता : मायावती

बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए)-2019 को लागू करने से जुड़े नियमों को अधिसूचित किए जाने के बाद सोमवार को कहा कि इस कानून को लेकर लोगों में जो संशय, असमंजस और आशंकाएं हैं, उन्हें दूर करने के बाद ही इसे लागू किया जाता तो बेहतर होता। बसपा प्रमुख ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा, ''केन्द्र सरकार द्वारा नागरिकता (संशोधन) अधिनियम को ठीक चुनाव से पहले लागू करने के बजाय इसको लेकर लोगों में जो संदेह, असमंजस और आशंकाएं हैं उन्हें पूरी तरह से दूर करने के बाद ही इसे लागू किया जाना ही बेहतर होता।''

लोगों के अधिकार छीनने का हो रहा खेल : ममता बनर्जी

ममता बनर्जी ने कहा, केंद्र सरकार ने कल सीएए लागू किया। मुझे संदेह है कि इनके द्वारा लाया गया कानून वैध भी या नहीं। इसे लेकर केंद्र सरकार की स्पष्टता नहीं है। साल 2019 में असम में एनआरसी के नाम पर 19 लाख में से 13 लाख बंगाली हिंदूओं को सूची से हटा दिया गया था। इसकी वजह से कई लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने आगे कहा, मैं पूछती हूं, अगर वे लोग दर्खास्त करेंगे तो क्या उन्हें नागरिकता मिलेगी? उनके बच्चे का भविष्य क्या होगा? उनकी संपत्ति का क्या होगा? इससे आपके सभी अधिकार छीन लिए जाएंगे, आपको अवैध घोषित कर दिया जाएगा। आपके पास कोई अधिकार नहीं बचेगा। यह अधिकार छीनने का खेला है। आपको डिटेंशन कैंप में ले जाया जाएगा। केंद्र सरकार सुन ले मैं बंगाल से किसी को भी जाने नहीं दूंगी।

लोकसभा चुनाव में जनता देगी जवाब : केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 को अधिसूचित करने का नरेन्द्र मोदी नीत केंद्र सरकार का कदम देश विरोधी है। उन्होंने दावा किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। केजरीवाल ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि सीएए लागू करना भाजपा की ''ओछी राजनीति'' है , जिसका मकसद पड़ोसी देशों के गरीब लोगों को भारत में अपना वोट बैंक बनाना है।

केजरीवाल ने एक्स पर कहा, ''10 साल देश पर राज करने के बाद चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार सीएए लेकर आयी है। ऐसे वक्त में जब गरीब और मध्यम वर्ग महंगाई से कराह रहा है और बेरोजगार युवा रोजगार के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहा है, उन असली मुद्दों का समाधान करने के बजाय ये लोग सीएए लाये हैं।'' आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि भाजपा कह रही है कि तीन पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा, ''इसका मतलब वे पड़ोसी देशों के लोगों को भारत में लाकर बसाना चाहते हैं। क्यों? अपना वोट बैंक बनाने के लिए। जब हमारे युवाओं के पास रोजगार नहीं है तो पड़ोसी देशों से आने वाले लोगों को रोजगार कौन देगा? उनके लिए घर कौन बनाएगा? क्या भाजपा उनको रोजगार देगी? क्या भाजपा उनके लिए घर बनाएगी?'' केजरीवाल ने कहा कि खासकर असम और पूरे पूर्वोत्तर के लोग सीएए का सख्त विरोध करते हैं, जो बांग्लादेश से होने वाले प्रवास के शिकार रहे हैं और जिनकी और संस्कृति आज खतरे में है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने असम और पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों को धोखा दिया है और जनता इसका जवाब लोकसभा चुनाव में देगी।

हिंदू महासभा के 'दो राष्ट्र' सिद्धांत की अवधारणा पर चल रही है : महबूबा

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने मंगलवार को आरोप लगाया कि नागरिकता (संशोधन) कानून (सीएए) को लागू करके भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) हिंदू महासभा के 'दो राष्ट्र' सिद्धांत की अवधारणा पर चल रही है। जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री रह चुकी महबूबा ने कहा कि उच्चतम न्यायालय में इस मामले के लंबित रहने के बावजूद सीएए को लागू करना सरकार की विफलताओं से ध्यान भटकाने का एक प्रयास है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के नेता यूसुफ तारिगामी ने आरोप लगाया कि सीएए का लागू किया जाना संविधान की आधारभूत संरचना के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि संविधान का आधार और भारत की नागरिकता की कसौटी किसी व्यक्ति के धर्म और पंथ से परे है, लेकिन सीएए को लागू करके इस आधार का सरासर उल्लंघन किया गया है। तारिगामी ने कहा कि सीएए को लागू करना सरकार की नाकामियों से ध्यान भटकाने का एक प्रयास है जिससे अल्पसंख्यकों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा।

सीएए के तहत कैसे मिलेगी नागरिकता

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के तहत पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू सिख बौद्ध जैन पारसी और ईसाई शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। आवेदक को सिर्फ यह साबित करना होगा कि वह 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गया था। इसके लिए नियम तय किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि दिसंबर 2019 में संसद के दोनों सदनों ने सीएए पारित किया था।

आवेदन के साथ देने होंगे ये दस्तावेज

आवेदक को वैध या समाप्त हो चुके पासपोर्ट, आवासीय परमिट, पति या पत्नी की भारतीय राष्ट्रीयता का प्रमाण मसलन, भारतीय पासपोर्ट या जन्म प्रमाणपत्र की प्रति या मैरेज रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाणपत्र की प्रति प्रदान करनी होगी। हालांकि, इन दस्तावेज को जमा करना अनिवार्य नहीं है।

ये होंगे पात्र

नागरिकता संशोधन कानून के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। 2014 से पहले भारत में रह रहे गैर मुस्लिम शरणार्थी इसके पात्र होंगे। आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन की सुविधा मिलेगी।

सरकार का यह है दावा

नागरिकता संशोधन कानून का उद्देश्य धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत में शरण लेने वालों की रक्षा करना है। सीएए में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों के लिए नागरिकता नियम को आसान बनाया गया है। आवेदक को सिर्फ यह साबित करना होगा कि वह 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आ गया था। इसके लिए नियम तय किए गए हैं।

जिद... सच की

Sanjay Sharma
editor.sanjaysharma
@Editor_Sanjay

बचपन को बचाने की जिम्मेदारी सबकी

उच्चतम न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस फैसले को भयावह करार दिया जिसमें कहा गया है कि बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री (चाइल्ड पोर्नोग्राफी) को केवल डाउनलोड करना और उसे देखना यौन अपराध से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कानून के तहत अपराध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी उचित है। हाईकोर्ट ने जो बात कही है वह बच्चों को यौन अपराध के बढ़ावे को उकसा सकता है। ऐसे में जितनी जल्द हो सकते शीर्ष अदालत इस मामले को सुनकर अपना फैसला दे दे ताकि बच्चों के बचपन को बचाया जा सके। दरअसल, उच्च न्यायालय के इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाई करने के लिए भी उच्च न्यायालय राजी हो गया। ज्ञात हो कि अदालत ने गत 11 जनवरी को 28 वर्षीय एक व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही भी निरस्त कर दी थी, जिस पर अपने मोबाइल फोन पर बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री डाउनलोड करने का आरोप था।

“ हाईकोर्ट ने जो बात कही है वह बच्चों को यौन अपराध के बढ़ावे को उकसा सकता है। ऐसे में जितनी जल्द हो सकते शीर्ष अदालत इस मामले को सुनकर अपना फैसला दे दे ताकि बच्चों के बचपन को बचाया जा सके। दरअसल, उच्च न्यायालय के इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाई करने के लिए भी उच्च न्यायालय राजी हो गया।

अदालत ने कहा था कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 ऐसी सामग्री को केवल देखने को अपराध नहीं बनाता है। मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा था है कि आजकल के बच्चे अश्लील सामग्रियां देखने की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं और समाज को वैसे बच्चों को दंडित करने के बजाय शिक्षित करने को लेकर पर्याप्त परिपक्वता दिखानी चाहिए। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने दो याचिकाकर्ता संगठनों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एच एस फुल्का की उन दलीलों पर गौर किया जिसमें उच्च न्यायालय के फैसले को कानूनों के विपरीत बताया गया। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, यह (उच्च न्यायालय का फैसला) भयावह है। एकल पीठ के न्यायाधीश ऐसा कैसे कह सकते हैं? नोटिस जारी करें जिसका तीन सप्ताह में जवाब दाखिल किया जाए। वरिष्ठ अधिवक्ता दो याचिकाकर्ता संगठनों- फरीदाबाद के जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस और नई दिल्ली स्थित बचपन बचाओ आंदोलन की ओर से पेश हुए। ये गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) बच्चों के कल्याण के लिए काम करते हैं। शीर्ष अदालत ने चेन्नई निवासी एस हरीश और तमिलनाडु के दो संबंधित पुलिस अधिकारियों से भी जवाब मांगा। उच्च न्यायालय ने हरीश के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम- 2012 और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम-2000 के तहत आपराधिक मामला रद्द कर दिया था। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर क्या फैसला देता है।

(इस लेख पर आप अपनी राय 9559286005 पर एसएमएस या info@4pm.co.in पर ई-मेल भी कर सकते हैं)

चीन के मंसूबों से सतर्क भी रहे भारत

डॉ. लक्ष्मी शंकर यादव

भारत व अमेरिका से लगातार चल रहे तनाव के बीच चीन ने एक बार फिर से अपने रक्षा बजट में भारी-भरकम बढ़ोतरी की है। चीन ने 7.2 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष 2024 का रक्षा बजट 1.67 ट्रिलियन युआन अर्थात? 232 अरब डॉलर कर दिया है। चीनी रक्षा बजट की यह वृद्धि बीते पांच सालों में सबसे ज्यादा है। दावा है कि अब चीन दुनिया में अमेरिका के बाद रक्षा बजट पर सबसे अधिक खर्च करने वाला दूसरा देश है। चीन की विधायिका की वार्षिक बैठक के उद्घाटन सत्र में 5 मार्च को आधिकारिक रक्षा बजट के आंक? की घोषणा की गई। विदेशी विशेषज्ञ मानते हैं कि यह धनराशि सत्तासीन कम्युनिस्ट पार्टी की सैन्य शाखा पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा किए गए खर्च का केवल एक अंश है।

चीनी रक्षा बजट भारतीय रुपयों में 19.23 लाख करोड़ रुपयों से ज्यादा है। चीन की तुलना में भारत का 2024-25 के लिए घोषित रक्षा बजट 621541 करोड़ रुपये है। इस तरह चीन का रक्षा बजट भारतीय रक्षा बजट से तीन गुना से भी ज्यादा है। चीन ने वर्ष 2023 में भी अपना रक्षा बजट 7.2 फीसदी तथा वर्ष 2022 में 7.1 फीसद बढ़ाया था। दरअसल, चीन दुनिया की नंबर एक सेना बनने की होड में रक्षा बजट में पिछले नौ वर्षों से लगातार इजाफा कर रहा है।

चीन ने अपना रक्षा बजट ऐसे समय बढ़ाया है जब उसकी अर्थव्यवस्था काफी बुरे दौर से गुजर रही है। पिछले साल चीन की आर्थिक ग्रोथ 5.2 प्रतिशत थी जबकि इस साल इसके 4.6 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। चीन की तेज आर्थिक ग्रोथ में एक लम्बे समय तक वहां की प्रॉपर्टी सेक्टर की विशेष भूमिका रही है। लेकिन फिलहाल प्रॉपर्टी सेक्टर की कुछ कंपनियां दिवालिया हो गई हैं और सरकार इनको उबारने के मूड में नहीं है। पहले आर्थिक ग्रोथ कम होने पर चीनी सरकार एक्सपोर्ट बढ़ाती थी और सरकारी मदद दी जाती थी पर अब ऐसा नहीं है। फिलहाल चीन सरकार ने इस साल के लिए 5 प्रतिशत ग्रोथ का लक्ष्य रखा है जो उसके मानक के हिसाब से कम है।

दरअसल, शी जिनपिंग ने अपनी सेना को वर्ष 2027 तक विश्वस्तरीय सेना बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। साथ ही चीनी सेना को वर्ष 2035 तक पूरी तरह से अत्याधुनिक बनाने का लक्ष्य भी है। इसी वजह से चीन अपना रक्षा बजट लगातार बढ़ा रहा है। शी जिनपिंग अपनी चीनी सेना को इतनी आधुनिक बनाना

चाहते हैं कि उनकी सेना संसार के किसी छोर पर या किसी भी देश के खिलाफ युद्ध में विजय हासिल कर सके।

दरअसल राष्ट्रपति शी जिनपिंग यह नहीं चाहते हैं कि उनके सैनिकों को युद्ध ल ?ने को रणक्षेत्र में उतरना पड़े। इसीलिए चीन अत्याधुनिक हथियार, मजबूत थियेटर कमांड, स्टील्थ तकनीक व लड़ाकू तकनीक के क्षेत्र में अधिक पैसा लगा रहा है। इनके विकास के बाद युद्ध में लड़ाकू जेट विमान, ऑटोनॉमस हथियार व अत्याधुनिक मिसाइलें बड़ी भूमिका निभाएंगी। हाल के वर्षों में चीन ने कई बड़े सैन्य सुधार किए हैं। दूसरे देशों में अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए नौसेना और वायुसेना को प्राथमिकता के आधार पर विस्तार दिया है। अब चीन नई रोबोट आर्मी तैयार कर चुका है और इसकी तैनाती भी भारतीय सीमा के नजदीक करनी शुरू कर दी है। उसने भारतीय सीमा के नजदीक आर्मी विलेज भी बसा दिए हैं।

चीन अमेरिका को पीछे छो ?ता हुआ दुनिया की सबसे बड़ी नौसैन्य ताकत बन रहा है। विगत दो तीन वर्षों में चीनी नौसेना में जितने युद्धपोत और पनडुब्बियां शामिल की गई हैं उतने शायद अमेरिका की नौसेना में न हों। इतने हथियारों की बढ़ोतरी के बाद भी उसकी भूख कम नहीं हुई है। चीन की रक्षा ताकत बढ़ाने वाली यह नीति आने वाले समय में विश्व को नए युद्ध में धकेलने में देर नहीं लगाएगी। इन योजनाओं का मकसद यही है कि चीन का अमेरिका, ताइवान, जापान व भारत के साथ जारी तनाव और हिन्द महासागर व दक्षिण चीन सागर में मिलने वाली चुनौतियों से निपटने में उसका सैन्य पक्ष कमजोर न पड़े।

चीन के नीति-नियन्ताओं के मुताबिक सेना को अत्याधुनिक बनाये जाने के फोकस को देखते हुए रक्षा बजट बढ़ाया गया है। चीन का ध्यान स्टील्थ लड़ाकू विमान, विमानवाहक पोत, सेटेलाइटरोधी मिसाइल समेत नई सैन्य क्षमता विकसित करने पर है। चीन अपना दबदबा बढ़ाने के लिए नौसेना की पहुंच को समुद्री क्षेत्रों में फैला रहा है। इस साल के रक्षा बजट का मुख्य जोर नौसेना के विकास पर रहेगा क्योंकि दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर पर उसके दावे तथा समुद्री आवागमन के लिहाज से इस क्षेत्र में तनाव बड़ा हुआ है। इसके अलावा एशिया प्रशांत क्षेत्र में अस्थिर सुरक्षा स्थिति को देखते हुए उसको जवाब के तौर पर तैयार होना है। दरअसल,चीन सैन्य क्षेत्र में दुनिया के शक्तिशाली देशों की तुलना में सबसे ऊपर रहना चाहता है। ऐसी स्थिति में भारत को चीन की रक्षा बढ़ोतरी से सजग रहने की आवश्यकता होगी।

उपभोक्ताओं को सब्सिडी दे रहे हैं किसान

देविंदर शर्मा

कई दशक पहले, प्रतिष्ठित प्रशासनिक अधिकारी एवं वैज्ञानिक डॉ. एमएस रंधावा ने एक लेख में किसानों और खेती के बारे में लोकप्रिय धारणा के बारे में बात की थी। एक किसान निस्संदेह बहुत मेहनती होता है। सर्दी हो, गर्मी हो या फिर बारिश आती हो; आप हमेशा उसे खेतों में कड़ी मेहनत करते हुए देख सकते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि किसानों ने अपने श्रम से, पसीना बहाकर अकेले ही देश को भूख के जंजाल से बाहर निकाला है।

लेकिन डॉ. रंधावा को उस समय समाज में प्रचलित एक किसान की स्वीकृत छवि से परेशानी हुई। आमजन की कल्पना में, किसान एक सादी पोशाक पहनता है, अक्सर एक मैला कुर्ता व धोती पहनता है और टूटी-टांके लगी धूल-धूसरित जूती पहनकर चलता है। उम्मीद रहती है कि आने-जाने के लिए ज्यादा से ज्यादा साइकिल इस्तेमाल करता है, और जब भी आप उसे दोपहिया वाहन चलाते हुए देखते हैं, तो अक्सर भौंहें तन जाती हैं। हालांकि अब वक्त बदल गया है लेकिन किसान और खेती के बारे में धारणा अब भी पूर्ववत ही कायम है।

साइकिल की जगह भले ही दोपहिया वाहन ले चुका है, जिसे अब कार द्वारा बदला जा चुका है, ऊपरी तबके में किसानों के पास कई बार शानदार मॉडल भी होते हैं, लेकिन एक पेशे के रूप में खेती के बारे में आमजन की सोच में बहुत बदलाव नहीं आया है। ग्रामीण-शहरी विभाजन का प्रतिबिंब, खेती अभी भी शहरी हाशिये पर बनी हुई है। मिसाल के तौर पर, यदि कोई किसान शहरी दायरे में प्रवेश करने की कोशिश करता है, तो उसे अभी भी नापसंद किया जाता है, और यहां तक कि खान-पान के तौर-तरीके अपनाता है, जिसमें मिसाल के तौर पर पिज्जा खाना भी शामिल है। इसके अलावा, ऐसे समय में जब एक घरेलू सहायिका को अपने कार्यस्थल तक जाने को स्कूटी चलाते हुए देखना असामान्य नहीं है, एक किसान द्वारा ट्रैक्टर पर महंगे म्यूजिक सिस्टम का उपयोग करना मंजूर नहीं है।

असल में, खेती एक दोयम दर्जा शब्द बन गया है। किसानों के प्रति इतनी गहरी उदासीनता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानूनी गारंटी की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी किसानों पर सवाल उठाने वाले प्रबल वृत्तांत के साथ ही तिरस्कार और अवमानना का भाव भी सामने आता है। विरोध कर रहे किसानों पर लगातार अपमानजनक शब्द कहे जा रहे हैं और मुख्यधारा के माध्यमों के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी अपमानजनक टिप्पणियां कृषक समुदाय के खिलाफ व्याप्त कुंठा के भावों का प्रतिबिंब हैं। आम तौर पर यह माना जाता है कि किसान बहुत पाला-पोसा जाता है, उन्हें भारी सब्सिडी व मुफ्त बिजली मिलती है, और वे इनकम टैक्स नहीं देते। किसानों की आय में कोई भी वृद्धि उपभोक्ता कीमतों पर असर डालेगी। जिसके परिणामस्वरूप खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ेगी इसलिए किसानों को बढ़ी हुई आय के अधिकार से वंचित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

चारों ओर इतनी गलत सूचनाएं, और त्रुटिपूर्ण आर्थिक तर्क उछाले जा रहे हैं कि मिथक व वास्तविकता में भेद करना आसान नहीं। किसी भी मामले में, नीति-निर्माता, अर्थशास्त्री और मीडिया फैलाए जा चुके भ्रम से खुश लगते हैं। चाहे वह काल्पनिक खाद्य मुद्रास्फीति के आंकड़े हों या राष्ट्रीय खजाने पर संभावित वित्तीय बोझ, सभी प्रकार के संदिग्ध आंकड़े प्रचलित हैं। मूल मान्यता यह है कि किसानों की आय में कोई भी बढ़ोतरी बाजार को बिगाड़ देगी और इससे व्यापार और उद्योग के मुनाफे में कमी आएगी। हकीकत में, जो स्वाभाविक से भी ज्यादा हो चुका है वह ये कि किसान को निरंतर गरीबी में रखने को लेकर देश संतुष्ट नजर आता है।

यदि किसान इतने लाड़ले होते तो मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि औसत कृषि आय निम्नतम स्तर पर बनी रहनी चाहिये थी। जो पहले कहा जा चुका है उसे दोहराने के जोखिम पर, कृषि परिवारों के लिए स्थितिजन्य आकलन सर्वेक्षण 2021 की नवीनतम रिपोर्ट की गणना के मुताबिक, कृषि परिवार की औसत मासिक आय 10,218 रुपये है। इससे यह भी पता चला कि खेती से होने वाली आय मनरेगा श्रमिकों की मासिक मजदूरी से भी कम थी। इससे भी बुरी बात, किसानों की स्थिति पर देश के एक अंग्रेजी दैनिक में बीती 23 फरवरी को प्रकाशित विवरण से पता चलता है कि पश्चिम बंगाल और ओडिशा जैसे राज्यों में औसत कृषि आय अभी भी कम है और 5,000 रुपये से 6,000 रुपये प्रति परिवार प्रति माह के बीच है। यहां तक ??कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी, जहां 90 प्रतिशत से अधिक किसान परिवार कर्जदार हैं, आय बहुत कम है। एक अध्ययन में यह पता चला है कि आंध्र प्रदेश के कई सूखा प्रभावित जिलों में लगभग 14 प्रतिशत पारिवारिक आय सरकारी योजनाओं से आती है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष आय मदद शामिल है। इसके अलावा, जैसा कि कुछ दिन पूर्व पेश 2022-23 घरेलू खर्च सर्वेक्षण से पता चलता है कि एक पेशेगत उद्यम के रूप में खेती कितनी अनिश्चित हो गई है, जिसमें कृषि परिवारों का खर्च ग्रामीण परिवारों से कम हो गया है। आय कम होने के कारण उपभोग कम है। इसलिए यह कहना कि किसान आयकर नहीं देते, उचित नहीं है। एक राष्ट्र के रूप में क्या यह हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि हम सबसे पहले किसानों को कर योग्य आय दें? किसी भी स्थिति में, यह उपभोक्ता केंद्रित नजरिया ही है जो असल में किसान को सही कीमत प्रदान करने से इनकार करता है। एक-दो साल को छोड़ दें तो व्यापार की शर्तें नकारात्मक रही हैं। कई अध्ययनों में सामने आया कि एक दशक से ज्यादा वक्त से ग्रामीण मजदूरी स्थिर है या फिर घट रही है। कृषक परिवारों के उपभोग स्तर में गिरावट भी यह इंगित करती है। और फिर भी, जैसे ही उच्चतर एमएसपी घोषित किया जाता है, अखबारों के संपादकीय लगभग हर बार इसे खाद्य मुद्रास्फीति में प्रत्याशित बढ़ोतरी से जोड़ने लगते हैं।

दरअसल, कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी सीएसीपी द्वारा जिन 23 फसलों के लिए एमएसपी की गणना करने के बाद उनकी कीमतों की घोषणा की जाती है, तो वह उनकी कीमतों की सिफारिश करने से पहले इनपुट-आउटपुट मूल्य समानता और बाजार कीमतों के रुझान पर गौर करता है। इसके अलावा, खाद्य मुद्रास्फीति को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित जायज सीमा के भीतर रखने से, लोगों को अक्सर यह अहसास नहीं होता है कि किसान वास्तव में उपभोक्ताओं और इस तरह देश की अर्थव्यवस्था को सब्सिडी देते हैं।

शलभासन

शलभासन के अभ्यास से स्लिप डिस्क और कमर दर्द से राहत मिलती है। इस आसन को करने के लिए पेट के बल जमीन पर लेटकर रीढ़ की हड्डी को मोड़ा जाता है। आसन को सही तरीके से करने से कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। शलभासन विशेष रूप से पीठ की मांसपेशियों को लक्षित करता है, जिसमें इरेक्टर स्पाइना, रॉमबॉइड्स और ट्रेपेज़ियस शामिल हैं। इस आसन के नियमित अभ्यास से इन मांसपेशियों को मजबूत बनाने और मुद्रा में सुधार करने में मदद मिलती है। यह आसन छाती, कंधों और जांघों को फैलाता और खोलता है, जिससे इन क्षेत्रों में समग्र लचीलेपन और गति की सीमा में सुधार होता है।

उष्ट्रासन

रीढ़ की हड्डी की समस्याओं को दूर करने के लिए उष्ट्रासन का अभ्यास असरदार है। इस आसन में शरीर ऊंट की मुद्रा में होता है। आसन को करने के लिए शरीर को पीछे की तरफ झुकाया जाता है। दबाव के कारण रीढ़ की हड्डी की समस्याएं दूर होती हैं। यह मुद्रा आपकी रीढ़ की गति की सीमा में सुधार करती है। उष्ट्रासन आपकी पीठ की मांसपेशियों को टोन करने में मदद करता है और आपके शरीर की मुद्रा को बढ़ाता है। यह योग करने से आपके पेट, छाती और पैर की मांसपेशियां टोन हो सकती हैं। उष्ट्रासन आपकी मूल शक्ति का निर्माण करके आपकी शारीरिक फिटनेस को लाभ पहुंचाता है। उष्ट्रासन आपकी भुजाओं और कंधों को फैलाता है और आपकी छाती के सामने के हिस्से को खोलता है। उष्ट्रासन आपके शरीर के ऊपरी और निचले हिस्से की मांसपेशियों को खींचता है।

शवासन

इस आसन को किसी भी योग के अभ्यास के बाद सबसे आखिर में किया जाता है। यह एक कठिन आसन है, जिसे अभ्यास के साथ ठीक तरीके से किया जा सकता है। शवासन के अभ्यास से शरीर और आंतरिक ऊर्जा बेहतर बनती है। स्लिप डिस्क की वजह से होने वाले दर्द को कम करने के लिए शवासन का अभ्यास कर सकते हैं।

स्लिप डिस्क की है समस्या तो करें ये योगासन

कमर और पीठ में दर्द सामान्य है लेकिन कई बार दर्द असहनीय हो जाता है। घंटों गलत पोस्चर में बैठने, गलत लाइफस्टाइल और खानपान के कारण स्लिप डिस्क की शिकायत हो जाती है। स्लिप डिस्क रीढ़ की हड्डी में होने वाली स्वास्थ्य संबंधी स्थिति है, जो सामान्यतः हड्डियों में खराबी और चोट लगने से हो सकती है। आजकल युवाओं में स्लिप डिस्क की शिकायत बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लगभग 80 फीसदी युवा स्लिप डिस्क की समस्या से परेशान हैं। स्लिप डिस्क की शिकायत होने पर आखिरी इलाज ऑपरेशन को माना जाता है। हालांकि समय रहते इस समस्या की पहचान कर सही इलाज लिया जा सकता है। इसके लिए योग भी एक असरदार इलाज प्रक्रिया है। स्लिप डिस्क के कारण होने वाले असहनीय दर्द को कम करने के लिए कुछ योगासनों का अभ्यास फायदेमंद हो सकता है।

भुजंगासन

भुजंगासन से रीढ़ की ऊपरी हड्डियों पर दबाव पड़ता है। इस योगासन में शरीर का आकार फन उठाए सांप जैसा होता है। कमर दर्द से राहत और शरीर को लचीला बनाने के लिए भुजंगासन का अभ्यास कर सकते हैं। इससे पूरी रीढ़ की हड्डी का तनाव दूर होकर लचीली बनने के साथ-साथ छाती और पीठ की तमाम खराबियां दूर होकर उनका विकास होता है। रीढ़ की हड्डी में यदि किसी प्रकार टेढ़ापन आ गया हो तो यह आसन नसों एवं मांसपेशियों को प्रभावित किये बिना ही उसे ठीक कर देता है। मेरुदण्ड की कोई हड्डी या कशेरुका अपने स्थान से हट गई हो तो भुजंगासन के अभ्यास से अपने स्थान पर वापस आ जाती है। इस आसन से कमर पतली तथा सीना चौड़ा होता है। यह आसन बढ़े हुए पेट तथा बैडोल कमर को ठीक अनुपात में लाकर उन्हें सुडौल तथा आकर्षक बनाता है। कद बढ़ता है। मोटापा दूर होकर सम्पूर्ण शरीर सुन्दर एवं कान्तिमान हो जाता है।

हंसना मना है

हम तो ऐसे ही उदासी में बैठे-बैठे पानी में पत्थर मार रहे थे, अचानक से एक मेंढ़क निकला और बोला, पानी में तो आ, तेरी उदासी उतारूं। तेरी वाली के चक्कर में तूने, मेरी वाली का सर फोड़ दिया।

सांता: डॉक्टर साहब, प्लास्टिक सर्जरी में कितना खर्चा आएगा? डॉक्टर: 50 हजार सांता: अगर प्लास्टिक मैं लेकर दूं तो? डॉक्टर: तो पिघला कर चिपका भी लेना।

एक सफल आदमी वो है जो अपनी बीवी के खर्च से ज्यादा कमा सके। एक सफल औरत वो होती है जो ऐसा आदमी खोज सके।

पापा: दिन भर फेसबुक पर बैठा रहता है, ये तुझे रोटी नहीं देने वाली, बेटा: पापा मुझे भी पता है रोटी नहीं देगी, पर रोटी बनाने वाली तो यही मिलेगी!

शादी करनी हो तो अपनी गर्लफ्रेंड से करो। दूसरों की गर्लफ्रेंड से तो, घरवाले भी करवा देते है।

पहला दोस्त - क्या कर रहे हो भाई? दूसरा दोस्त - खा रहा हूं भाई...पहला दोस्त- अकेले-अकेले...? दूसरा दोस्त- अबे बीवी से ताने खा रहा हूं, आजा तू भी खा ले...!

कहानी | जैसे को तैसा

एक बार की बात है सीतापुरी गांव में जीर्णधन नाम का एक बनिया रहता था। उसका काम कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, इसलिए उसने धन कमाने के लिए विदेश जाने का फैसला किया। उसके पास कुछ ज्यादा पैसे या कोई कीमती वस्तु नहीं थी। सिर्फ उसके पास एक लोहे का तराजू थी। उसने वो तराजू साहूकार को धरोहर के रूप में दे दिया और बदले में कुछ रुपये ले लिए। जीर्णधन ने साहूकार से कहा कि वह विदेश से लौटकर अपना उधार चुका कर तराजू वापस ले लेगा। जब दो साल बाद वह विदेश से लौटा, तो उसने साहूकार से अपना तराजू वापस मांगा। साहूकार बोला कि वो तराजू तो चूहों ने खा लिया। जीर्णधन समझ गया कि साहूकार की नियत खराब हो गई है और वह तराजू वापस करना नहीं चाहता। तभी जीर्णधन के दिमाग में एक चाल सूझी। उसने साहूकार से कहा कि कोई बात नहीं अगर तराजू चूहों ने खा लिया है, तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सारी गलती उन चूहों की है। थोड़ी देर बाद उसने साहूकार से कहा कि दोस्त मैं नदी में नहाने जा रहा हूं। तुम अपने बेटे धनदेव को भी मेरे साथ भेज दो। वो भी मेरे साथ नहा आएगा। साहूकार, जीर्णधन के व्यवहार से बहुत खुश था, इसलिए उसने जीर्णधन को सज्जन पुरुष जानकर अपने बेटे को उसके साथ नहाने के लिए नदी पर भेज दिया। जीर्णधन ने साहूकार के बेटे को नदी से से कुछ दूर ले जाकर एक गुफा में बंद कर दिया। उसने गुफा के दरवाजे पर बड़ा-सा पत्थर रख दिया, जिससे साहूकार का बेटा बचकर भाग न पाए। साहूकार के बेटे को गुफा में बंद करके जीर्णधन वापस साहूकार के घर आ गया। उसे अकेला देखकर साहूकार ने पूछा कि मेरा बेटा कहां है। जीर्णधन बोला कि माफ करना दोस्त तुम्हारे बेटे को चील उठाकर ले गई है। साहूकार हैरान रह गया और बोला कि ये कैसे हो सकता है? चील इतने बड़े बच्चे को कैसे उठा ले जा सकती है? जीर्णधन बोला जैसे चूहे लोहे के तराजू को खा सकते हैं, वैसे ही चील भी बच्चे को उठाकर ले जा सकती है। अगर बच्चा चाहिए, तो तराजू लौटा दो। जब अपने ऊपर मुसीबत आई तब साहूकार को अक्ल आई। उसने जीर्णधन का तराजू वापस कर दिया और जीर्णधन ने साहूकार के बेटे को आजाद कर दिया।

7 अंतर खोजें

पंडित संदीप आत्रेय शास्त्री

जानिए कैसा रहेगा कल का दिन

लेखक प्रसिद्ध ज्योतिषविद हैं। सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कॉल करें-9837081951

मेष बकाया वसूली के प्रयास सफल रहेंगे। व्यावसायिक यात्रा मनोनुकूल लाभ देगी। लाभ के मौके बार-बार प्राप्त होंगे। विवेक का प्रयोग करें। बेकार बातों में समय नष्ट न करें।

वृषभ कोई पुरानी व्याधि परेशानी का कारण बनेगी। विरोधी सक्रिय रहेंगे। कोई बड़ी समस्या से सामना हो सकता है। नई योजना बनेगी। कार्यप्रणाली में सुधार होगा।

मिथुन धर्म-कर्म में रुचि बढ़ेगी। कोर्ट व कचहरी के अटके कामों में अनुकूलता आएगी। व्यापार-व्यवसाय ठीक चलेगा। निवेश शुभ रहेगा।

कर्क बोलचाल में हल्के शब्दों के प्रयोग से बचें। प्रतिद्वंद्विता कम होगी। शत्रु सक्रिय रहेंगे। जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। वाहन व मशीनरी के प्रयोग में लापरवाही न करें।

सिंह कोर्ट व कचहरी में लंबित कार्य पूरे होंगे। जीवनसाथी से सहयोग प्राप्त होगा। व्यापार-व्यवसाय मनोनुकूल रहेगा। घर-बाहर प्रसन्नता रहेगी। शेयर मार्केट से लाभ होगा।

कन्या रोजगार में वृद्धि तथा बेरोजगारी दूर होगी। आर्थिक उन्नति के प्रयास सफल रहेंगे। नौकरी में प्रभाव बढ़ेगा। शेयर मार्केट में सोच-समझकर निवेश करें।

तुला किसी आनंदोत्सव में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। यात्रा लाभदायक रहेगी। विद्यार्थी वर्ग सफलता प्राप्त करेगा। व्यापार मनोनुकूल रहेगा।

वृश्चिक व्यवसाय ठीक चलेगा। आय में कमी रह सकती है। दुःखद समाचार की प्राप्ति संभव है। व्यर्थ भागदौड़ रहेगी। काम में मन नहीं लगेगा।

धनु जल्दबाजी में कोई काम न करें। पुराना रोग परेशानी का कारण बन सकता है। कोई आवश्यक वस्तु गुम हो सकती है। चिंता तथा तनाव रहेंगे।

मकर किसी भी निर्णय को लेने में जल्दबाजी न करें। भ्रम की स्थिति बन सकती है। लेन-देन में सावधानी रखें। थकान व कमजोरी महसूस होगी। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी।

कुम्भ अप्रत्याशित खर्च सामने आएंगे। कर्ज लेना पड़ सकता है। मस्तिष्क पीड़ा हो सकती है। घर-बाहर सहयोग प्राप्त होगा। भेंट व उपहार की प्राप्ति संभव है।

मीन आंखों को चोट व रोग से बचाएं। कीमती वस्तु गुम हो सकती है। पुराना रोग उभर सकता है। दूसरों के झगड़ों में न पड़ें। हल्की हंसी-मजाक किसी से भी न करें।

बॉलीवुड | मन की बात

मुझे वर्दी के प्रति है अधिक प्यार : सिद्धार्थ मल्होत्रा

बॉलीवुड अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा अपनी आगामी फिल्म योद्धा को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। इस फिल्म में उनके साथ दिशा पाटनी और राशि खन्ना भी अहम भूमिका में हैं। इस फिल्म का निर्देशन सागर अंब्रे और पुष्कर ओझा द्वारा किया गया है, और यह धर्मा प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित है। दर्शकों को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। सिद्धार्थ अब तक देशभक्ति से भरी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। इनमें शेरशाह, मिशन मजनू, वेब सीरीज भारतीय पुलिस बल और अब योद्धा शामिल है। अभिनेता ने देशभक्ति से जुड़े अपने किरदारों के लेकर हाल ही में बातचीत की है। सिद्धार्थ मल्होत्रा से हाल ही में एक के बाद एक देशभक्ति वाली फिल्में करने के बारे में पूछा गया, तो इस पर उन्होंने कहा कि यह कोई सोच-समझकर उठाया गया कदम नहीं था। अभिनेता ने कहा, मुझे लगता है कि यह बस संयोग से हुआ। मैं शायद वर्दी के प्रति थोड़ा अधिक प्यार है। किसी भी प्रकार की परवाह किए बिना एक आदमी पर वर्दी से बेहतर कुछ भी नहीं दिखता है। सिद्धार्थ ने नई दिल्ली में योद्धा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, यह एक काल्पनिक वर्दी है, इसलिए हमने सेना बनाई है, हमने पुलिस बनाई है, मैंने अपनी योद्धा टीम बनाई है। ताकि मैं यहां वर्दी पहन सकूं। इसके साथ उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वह रोमांटिक किरदार निभाने के विचार से पूरी तरह से अलग नहीं हुए हैं। अभिनेता ने कहा, योद्धा भी एक लव स्टोरी का संकेत है, जैसा कि आप ट्रेलर में देख सकते हैं। हालांकि ये पूरी तरह से लव स्टोरी नहीं है। उन्होंने आगे कहा, हम यही पर हैं और धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म का प्रचार कर रहे हैं, इसलिए करण जौहर से पूछना चाहिए कि वह मेरे लिए अपनी अगली रोमांटिक फिल्म कब बना रहे हैं। बता दें कि योद्धा एक बहादुर सैनिक की कहानी है जो एक अपहृत विमान के यात्रियों को बचाने के लिए सभी बाधाओं से लड़ता है। योद्धा का निर्माण करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शंस और शशांक खेतान की मेंटर डिसिप्लिन फिल्म्स द्वारा किया गया है। यह फिल्म 15 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। उम्मीद है कि योद्धा स्क्रीन पर धमाल मचा देगी, क्योंकि सिद्धार्थ मल्होत्रा ने एक बार फिर एक्शन हीरो के रूप में अपनी क्षमता साबित की है।

हम दिल की सुनते थे और बिना पीआर के काम करते थे : करिश्मा

करिश्मा कपूर बॉलीवुड के मशहूर नामों में से एक हैं। उन्होंने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हैं। इन दिनों वे अपनी आने वाली फिल्म मर्डर मुबारक को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं। इस फिल्म वे सारा अली खान और पंकज त्रिपाठी जैसे कलाकारों के साथ नजर आने वाली हैं। हाल ही में अभिनेत्री अपने करियर के उतार-चढ़ाव और मर्डर मुबारक के बारे में मीडिया से बात करती दिखाई दीं। करिश्मा कपूर मर्डर मुबारक से बॉलीवुड में फिर से वापसी करने जा रही हैं। इस फिल्म का निर्देशन होमी अदजानिया ने किया है। मर्डर मुबारक के प्रमोशन के दौरान जब उनसे पूछा गया कि आप इन दिनों बॉलीवुड में क्या बदलाव महसूस करती हैं। इस सवाल के जवाब में करिश्मा कहती हैं, सच कहूं तो अब काफी सारी चीजें बदल गई हैं। हम तब दिल की सुनते थे और जो सही लगता था, वह फिल्म कर लेते थे। किसी चीज के लिए हिसाब-किताब नहीं करते थे। करिश्मा कपूर अपनी बात जारी रखते हुए कहती हैं, तब हमारे पास कोई पीआर टीम और स्टाइलिश नहीं होता था। सब कुछ हमलोग खुद ही हैंडल करते थे। हम सेट पर जाते थे और शूटिंग शुरू कर देते थे। न तो हमें कोई सलाह देने के लिए होता था न ही कोई ये समझाने के लिए कि यह फिल्म सही नहीं है या फिर इसे करो। बस काम करने के लिए मन में एक जुनून था, इसलिए काम करते चले गए। करिश्मा कपूर अपनी फिल्मों के बारे में बातें करते हुए कहती हैं, वैसे मैंने कभी यह सोच कर कोई फिल्म या गाना नहीं किया कि इससे मेरे करियर में बदलाव आएगा या फिर फायदा पहुंचेगा, लेकिन अगर मैं पीछे मुड़कर देखती हूं तब लगता है हीरो नंबर 1 के बाद मेरे लिए सब कुछ बदल गया। उस फिल्म की सफलता मेरे करियर के लिए वरदान साबित हुई। इस फिल्म के बाद राजा हिंदुस्तानी और दिल तो पागल है जैसी फिल्में मेरे हिस्से में आई थीं।

मेरे बाबा स्टार नहीं थे और मैं स्टारकिड नहीं हूं : बाबिल

बॉलीवुड | मसाला

बाबिल खान दिवंगत अभिनेता इरफान खान के बेटे हैं। पिछले दिनों वे वेब सीरीज द रेलवे मेन में नजर आए थे। दर्शकों को उनका काम इस सीरीज में काफी पसंद आया था। हाल ही में एक साक्षात्कार के दौरान अभिनेता अपने बचपन के दिनों को याद करते दिखे। साथ ही साथ उन्होंने फिल्म बिल्लू बार्बर और शाहरुख खान से जुड़े कई दिलचस्प किस्सों को भी साझा किया। बाबिल खान धीरे-धीरे ही सही बॉलीवुड में अपनी जगह बना रहे हैं। दर्शक उनके काम को सराह भी रहे हैं। पिछले दिनों एक इंटरव्यू के दौरान वे बचपन के दिनों को याद करते हुए बोले, जिन दिनों बाबा बिल्लू बार्बर में काम कर रहे थे, उन दिनों मैं काफी छोटा था। मैं कभी-कभी सेट पर उनके साथ चला जाता था। एक दिन मैं सेट पर था कि अचानक ही मुझे शाहरुख खान दिखे। मैं उन्हें देखते ही उनकी तरफ भागा और उनके पैरों से लिपट गया था। बाबिल अपनी बात जारी रखते हुए कहते हैं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं सिर्फ इतना महसूस कर रहा था कि ये शाहरुख खान हैं, जिन्हें मैं काफी पसंद करता हूं। मैं उनके पैरों से लिपटा हुआ था और वे धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने बड़े प्यार से मेरे माथे पर अपना हाथ फिराया था। मुझे आज भी याद है जब वे सेट पर आए थे, तब उनके पीछे-पीछे कितनी बड़ी भीड़ भी वहां पहुंच गई थी। जब बाबिल से पूछा गया कि वे बॉलीवुड की पार्टियों में क्यों नहीं दिखाई देते हैं। इस सवाल के जवाब में वे कहते हैं, देखिए मेरे बाबा न तो स्टार थे और न ही मैं स्टार किड हूं, जो मुझे पार्टियों में बुलाया जाएगा। बाबा कभी भी ऐसी कॉमर्शियल पार्टी या फिल्मों का हिस्सा नहीं रहे। आप उन्हें किसी बॉक्स में नहीं फिक्स कर सकते और दूसरी बात मुझे अकेले रहना भी पसंद है इसलिए मैं इन पार्टियों में नहीं जाता हूं।

अजब-गजब | गहने रखने के लिए सालों पहले जब नहीं थे बैंक

घने जंगलों-पहाड़ों पर बनते थे लॉकर

क्या आपने कभी सोचा है कि जब सालों-साल पहले बैंक नहीं हुआ करते थे, तब लोग अपनी दौलत, गहने-जेवरात को कहां छुपा कर रखते थे? ताकि वे लूटेरों से अपनी जमा-पूंजी को सुरक्षित रख सकें? शायद नहीं जानते होंगे। उस दौरान लोग अपने घरों में मजबूत से मजबूत तिजोरी बनवाते थे। वहीं, जिनके पास ज्यादा पैसे होते थे, वो लोग घर के अंदर गुप्त तिजोरियों का निर्माण करवाते थे। ऐसे में कोई आक्रमणकारी या फिर लूटेरा अगर लूटने के लिहाज से उनके घर के अंदर आ जाए, तो उनकी नजर से वो अपनी दौलत को बचा सके। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे, जो जंगल के बीचों-बीच पहाड़ में अपने लिए तिजोरियां बनवा लेते थे। ऐसा इसलिए ताकि प्राकृतिक दिखने वाली चट्टान के अंदर देखने का ख्याल शायद ही कभी किसी के मन में आए। इसी तरह की तिजोरी से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि चट्टान को बिना नुकसान पहुंचाए, बिल्कुल उसी के शेप में एक तिजोरी का निर्माण पहाड़ के तलहटी में किया गया है। इसे इतनी कुशलतापूर्वक बनाया गया है कि किसी को इसके बारे में पता ही नहीं चलेगा। ऐसे में बड़े आराम से यहां पर कीमती सामान को संग्रहित किया जा सकता है। इससे लूटेरे भी चकमा खा

जाते थे और लोगों का अनमोल सामान बिल्कुल सुरक्षित रहता था। इस वीडियो को डिस्कवर द वर्ल्ड नाम के यूजर ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक शख्स पहाड़ के नीचे मौजूद एक टुकड़े को बाहर खिंचता है। उसके अंदर काफी खाली जगह है, जिसमें खजाने को छुपाकर रखा जाता था। वहीं, दरवाजे पर भी पत्थर लगाए गए हैं, जिससे बाहर से किसी को इसके बारे में कुछ पता भी नहीं चल सकता। देखने में ऐसा लगता है मानो वो उस पहाड़ का हिस्सा हो। बता दें कि इस तरह की तिजोरियों का निर्माण सालों-साल पहले होता था, तब बैंक नहीं हुआ करते थे। हालांकि, ये वीडियो कहां का है, इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है। दुनिया का सबसे पहला बैंक इटली के टस्कन सिटी ऑफ सिएना में 1472 ईस्वी में बना था, जिसका नाम बांका मोन्टे देई पाश्री दी सिएना था। वहीं, भारत का पहला बैंक 1770 में खुला था, जिसका नाम बैंक ऑफ हिन्दुस्तान था। यह बैंक 1832 में बंद हो गया। वहीं, आजादी के पहले लगभग 600 बैंक भारत में रजिस्टर्ड थे, लेकिन कुछ बैंक ही आजादी के बाद बचे रहे। उस दौरान लोगों को बैंक पर ज्यादा भरोसा नहीं हुआ करता था।

भारत का ऐसा कॉलेज जहां हेलमेट पहनकर पढ़ते हैं छात्र, इमारत की कभी भी गिर सकती है छत

भारत में कई तरह के कॉलेज आपको नजर आ जायेंगे। लोग प्लेसमेंट और कॉलेज की सुविधाओं के आधार पर इनमें एडमिशन लेते हैं। कई लोग सरकारी कॉलेज में पढ़ना प्रेफर करते हैं। इनमें फीस कम होती है और इनके डिग्री की वैल्यू ज्यादा होती है। वहीं प्राइवेट कॉलेज बेहतरीन सुविधाएं तो देते हैं लेकिन साथ ही मोटी फीस भी वसूलते हैं। लेकिन जमशेदपुर के मानगो के वर्कर्स कॉलेज के हालात कुछ अलग हैं। इस वर्कर कॉलेज में पढ़ाई करने आने वाले स्टूडेंट्स हेलमेट पहनकर क्लास में बैठते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये कोई यूनिक ड्रेस कोड है तो आप गलत हैं। दरअसल, इन स्टूडेंट्स के हेलमेट पहनने के पीछे एक खास वजह है। इन छात्रों का क्लास में हेलमेट पहनकर पढ़ाई करने का एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, जहां से ये वायरल हो गया है। क्लास में हेलमेट पहनकर बैठे ये छात्र मजबूर हैं। दरअसल, इस कॉलेज की इमारत काफी पुरानी हो चुकी है। इसकी अवस्था इतनी जर्जर है कि छत कभी भी गिर सकती है। ऐसे में छात्र अपनी सुरक्षा के लिए क्लास के अंदर हेलमेट पहनकर बैठते हैं। कई छात्रों के ऊपर छत का कुछ हिस्सा गिर चुका है। इस वजह से स्टूडेंट्स का कहना है कि अगर क्लास करनी है तो उनके पास एक यही विकल्प बचता है। जब इस वीडियो के वायरल होने के बाद कॉलेज के प्रिंसिपल से बात की गई, तो उसने भी लाचारी जताई। कॉलेज के प्रिंसिपल एसपी महालिक के मुताबिक़, इमारत को बने सत्तर से अधिक वर्ष हो चुके हैं। उन्होंने कई बार इसके जर्जर हालत के बारे में आला अधिकारियों को बताया लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। ऐसे में उनके पास पढ़ाई को इसी हाल में जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

सीएए से फूट पड़ेगी, कोई लाभ नहीं मिलेगा : स्टालिन

» बोले सीएम- तमिलनाडु सरकार लागू नहीं करेगी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) को विभाजनकारी और बेकार बताते हुए इसे खारिज कर दिया और कहा कि इसे उनके राज्य में लागू नहीं किया जाएगा। स्टालिन ने लोकसभा चुनाव नजदीक होने के बीच सीएए लागू करने के लिए नियमों को जल्दबाजी में अधिसूचित करने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सीएए और इसके नियम संविधान की मूल संरचना के खिलाफ हैं।

उन्होंने कहा, सीएए से कोई लाभ नहीं होने वाला है। यह भारतीय जनता के बीच सिर्फ फूट डालने का रास्ता तैयार करेगा। उनकी सरकार का रुख यह है कि यह कानून पूरी तरह अनुचित है और इसे निरस्त किया जाना चाहिए। स्टालिन ने कहा, इसलिए, तमिलनाडु सरकार राज्य में सीएए लागू करने का किसी भी तरीके से कोई अवसर नहीं देगी। राज्य में सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के अध्यक्ष स्टालिन ने दोहराया कि सीएए बहुलवाद, धर्मनिरपेक्षता, अल्पसंख्यक समुदायों और श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों के खिलाफ है।

अगर एनआरसी के लिए आवेदन न करने वाले एक भी व्यक्ति को नागरिकता मिली तो इस्तीफा दे दूंगा : हिमंत

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि अगर राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के लिए आवेदन नही करने वाले किसी व्यक्ति को नागरिकता मिल जाती है तो वह इस्तीफा देने वाले पहले व्यक्ति होंगे। उनकी यह टिप्पणी सोमवार को विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (सीएए) को लागू करने पर विपक्षी दलो द्वारा केंद्र सरकार की आलोचना और पूरे असम मे हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच आई है। नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से दिसंबर, 2014 से पहले भारत आए गैर-मुस्लिम प्रवासियो- हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायो के लोगो को भारत की नागरिकता प्रदान करने की अनुमति देता है। मुख्यमंत्री ने कहा, मैं असम का बेटा हूं और अगर एनआरसी के लिए आवेदन नही करने वाले एक भी व्यक्ति को नागरिकता मिलती है, तो मै इस्तीफा देने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा। प्रदर्शनकारियो का दावा है कि सीएए लागू होने पर लाखो लोग राज्य मे प्रवेश करेगे। शर्मा ने कहा, अगर ऐसा होता है तो मै विरोध करने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा।

संविधान का उल्लंघन करता है सीएए: येचुरी

नई दिल्ली। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) के तहत नियमो को अधिसूचित किए जाने का विरोध करते हुए दावा किया कि यह नागरिकता को धार्मिक पहचान से जोड़कर संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतो का उल्लंघन करता है। वामपंथी दल ने एक बयान मे यह आरोप भी लगाया कि नियमो का क्रियान्वयन राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) से जुड़ा हुआ है। उसने यह यह आशंका भी जताई कि मुस्लिम नागरिको को निशाना बनाया जाएगा। माकपा पोलित ब्यूरो नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) के तहत नियमो को अधिसूचित किए जाने का कड़ा विरोध करता है। सीएए नागरिकता को धार्मिक पहचान से जोड़कर संविधान मे निहित नागरिकता के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत का उल्लंघन करता है। माकपा महासचिव सीताराम एचुरी ने एक्स पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव से पहले सीएए के नियमो को अधिसूचित करने का उद्देश्य सांप्रदायिक विभाजन को तेज करना है।

राजनीतिक लाभ के लिए भाजपा लाई सीएए : पलानी

चेन्नई। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) महासचिव ए के पलानीस्वामी ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) के लागू होने की आलोचना की और कहा कि केंद्र सरकार ने इसके कार्यान्वयन के साथ एक ऐतिहासिक भूल की है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा करने का आरोप लगाया है। अन्नाद्रमुक इस कदम की कड़ी निंदा करती है, जिसका उद्देश्य राजनीतिक लाभ लेने के लिए लोकसभा चुनाव से पहले लोगो को विभाजित करना है। जबकि इसे पिछले पांच वर्षो से लागू नही किया गया था। राज्य विधानसभा मे नेता प्रतिपक्ष पलानीस्वामी ने सोमवार देर रात सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट मे कहा, केंद्र सरकार ने इसे लाकर एक ऐतिहासिक भूल की है। अन्नाद्रमुक इसे स्वदेशी लोगो - मुसलमानो और श्रीलंकाई तमिलो के खिलाफ लागू करने के किसी भी प्रयास की अनुमति नही देगी। अन्नाद्रमुक देश के लोगो के साथ मिलकर लोकतांत्रिक तरीके से इसका विरोध करेगी। नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ्गानिस्तान से दिसंबर, 2014 से पहले भारत आए गैर-मुस्लिम प्रवासियो- हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायो के लोगो को भारत की नागरिकता प्रदान करने की अनुमति देता है।

सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ओवैसी, बोले- एनपीआर और एनआरसी भी आएगा

हैदराबाद। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने नागरिकता (संशोधन) कानून (सीएए) के संविधान के खिलाफ होने का आरोप लगाते हुए कहा कि अधिनियम के नियमो को अधिसूचित किए जाने के मद्देनजर वह उच्चतम न्यायालय का रुख करेंगे। ओवैसी ने कहा कि धर्म के आधार पर कोई कानून नही बनाया जा सकता और इसपर उच्चतम न्यायालय के कई निर्णय भी है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख ने यहां कहा, ...यह समानता के अधिकार के खिलाफ है। आप प्रत्येक धर्म के लोगो को (नागरिकता की) अनुमति दे रहे है, लेकिन इस्लाम धर्म के लोगो को यह नही दे रहे है। ओवैसी ने दावा किया कि सीएए को राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी (एनपीआर) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए। उन्होने कहा, यह सरकार चार साल बाद (सीएए के) नियम बना रही। मै देश को यह बताना चाहता हूं। ओवैसी ने कहा, मै कहना चाहता हूं कि केवल सीएए को ही मत देखिए। आपको इसे एनपीआर और एनआरसी के साथ देखना होगा। जब वह होगा तब बेशक निशाने पर मुख्य रूप से मुसलमान, दलित, आदिवासी और गरीब होंगे।

रोड शो से पीएम मोदी को घेरेंगी ममता बनर्जी

» सीएए के खिलाफ सिलीगुड़ी में दहाड़ेंगी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार को संशोधित नागरिकता कानून (सीएए)-2019 को लागू करने के खिलाफ सिलीगुड़ी में एक रोडशो का नेतृत्व करेंगी। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रमुख ममता बनर्जी ने दावा किया कि अधिसूचित नियम 'असंवैधानिक और भेदभावपूर्ण' है।

ममता की पार्टी ने एक बयान में कहा कि टीएमसी सिलीगुड़ी में सीएए-एनआरसी के खिलाफ रोडशो करेगी। हमारी अध्यक्ष ममता बनर्जी रोड शो का नेतृत्व करेंगी।'' उत्तर 24 परगना जिले के हाबरा में एक आधिकारिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि वह पश्चिम बंगाल में सीएए को लागू करने की अनुमति नहीं देंगी। उन्होंने लोगों से इस कानून के तहत नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने से पहले 'कई बार' सोचने का आग्रह किया। केंद्र सरकार ने सोमवार को सीएए को लागू किया। केंद्र ने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर-मुस्लिम प्रवासियों को तेजी से नागरिकता प्रदान करने के लिए सीएए के नियमों को अधिसूचित किया था।

शाहजहां शेख की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

कोलकाता। कलकत्ता हाईकोर्ट ने निलंबित टीएमसी नेता शाहजहां शेख की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दी। कथित राशन वितरण घोटाले मामले में कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। प्रवर्तन निदेशालय मामले की जांच कर रहा है। ईडी ने इस मामले में पश्चिम बंगाल की पूर्व मंत्री ज्योति प्रिया मल्लिक को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास 2011 से 2021 तक खाद्य और आपूर्ति विभाग था।

न्यायमूर्ति देबांगसु बसाक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने शेख के वकील और ईडी की दलीलें सुनने के बाद उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। शेख वर्तमान में सीबीआई की हिरासत में है। दरअसल, पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में उसके परिसर की तलाशी लेने गए ईडी अधिकारियों पर भीड़ ने हमला कर दिया था। मामला पांच जनवरी को है। उन्हें राज्य पुलिस ने 29 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि सीबीआई, ईडी या पश्चिम बंगाल पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने भीड़ के हमले से जुड़े मामलों की जांच अपने हाथ में ली है।

धीरे-धीरे चढ़ने लगा पारा गर्मी ने बढ़ाई परेशानी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। चढ़ता पारा, धूप की तल्खी मार्च महीने में अब परेशान करने लगी है। आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने पारे में दो से तीन डिग्री तक बढ़ोतरी का अनुमान जताया है। वहीं 13 मार्च बुधवार से 18 मार्च तक प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में रुक-रुक कर बारिश के भी आसार जताए जा रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को चक्रवातीय दबाव का असर दिखेगा।

» बारिश होने के आसार

पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश के आसार हैं। 14 और 15 को मौसम शुष्क रहेगा। 16 मार्च को फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश के आसार हैं। यह सिलसिला 18 तक लगातार रह सकता है। इन सबके बीच मंगलवार का दिन अन्य दिनों के मुकाबले ज्यादा गर्म रहा। ज्यादातर इलाकों में पारा सामान्य से अधिक दर्ज किया गया। प्रयागराज में अधिकतम तापमान सबसे ज्यादा 34.8 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड हुआ। प्रदेश में अधिकतम तापमान 28 से 34.8 डिग्री के बीच रहा।

लखनऊ में दिन का पारा 32 डिग्री पार

लखनऊ में अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो इस सीजन में अभी तक सर्वाधिक रहा। न्यूनतम तापमान 15.6 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक, चढ़ता पारा आने वाले समय में गर्मी के और बढ़ने का संकेत दे रहा है।राजधानी के दिन के तापमान में सोमवार की तुलना में 2.1 डिग्री की वृद्धि रही। सोमवार को यह 30.4 डिग्री था। न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री बढ़ा, जो सोमवार को 14.2 डिग्री सेल्सियस था। अतुल कुमार सिंह के मुताबिक, हवा की रफ्तार धीमी होने के साथ पारे में दो से तीन डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है।

टी-20 वर्ल्डकप से बाहर हो सकते हैं कोहली

» धीमी विकेट का हवाला देकर टीम में नहीं किये जायेंगे शामिल

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए 30 अप्रैल तक सभी टीमों का ऐलान हो जाएगा। बीसीसीआई को भी अपनी टीम अप्रैल के आखिरी सप्ताह या मई के पहले सप्ताह में फाइनल करनी होगी। हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक विराट कोहली को स्क्वॉड से बाहर रखा जा सकता है। इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है कि वेस्टइंडीज और यूएसए में विकेट धीमे होंगे। ऐसे में उनकी बल्लेबाजी स्टाइल से भारत को फायदा नहीं होगा।

हालांकि, एक लाइफलाइन कोहली के पास आईपीएल 2024 है, जिसमें वो बेहतरीन प्रदर्शन करके खुद की जगह बचा सकते हैं। टी20 वर्ल्ड कप टीम में जगह बनाने के लिए विराट कोहली को आईपीएल 2024 में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। चयनकर्ता कोहली को टी20 वर्ल्ड कप के लिए चुनने के इच्छुक नहीं हैं, क्योंकि प्रबंधन का मानना है कि अनुभवी खिलाड़ी सबसे छोटे प्रारूप में टीम की जरूरतों को पूरा करने में विफल रहे हैं। कोहली ने टी20 वर्ल्ड कप 2022 के बाद से कोई टी20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है। वे रोहित शर्मा के साथ अफगानिस्तान टी20 सीरीज में खेले थे, लेकिन ज्यादा सफल नहीं हो पाए थे। दो ही मैच उन्होंने खेले थे।

वहीं बोर्ड के सचिव जय शाह ने टी20 वर्ल्डकप के लिए रोहित शर्मा को कप्तान बनाए जाने की पुष्टि की है। हालांकि, जब उनसे विराट कोहली के टी20 भविष्य के बारे में पूछा गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली। रिपोर्ट में कहागया है कि बोर्ड ने कोहली के चयन की गुत्थी मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर पर छोड़ दी है। ये बहुत नाजुक मामला है। ऐसे में लोग इसमें शामिल होने के इच्छुक नहीं हैं।

हरियाणा विस में विश्वास मत प्रस्ताव पर हंगामा

हुड्डा ने सत्र बुलाने पर उठाया सवाल, एक सदस्य के लिए हाउस स्थगित नहीं कर सकते : स्पीकर

कांग्रेस विधायक का तंज- पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर को बेआबरू कर बाहर निकाला गया

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

चंडीगढ़। हरियाणा में एक दिन की नायब सिंह सैनी सरकार सदन में अपना विश्वास मत हासिल करने का प्रस्ताव पारित कर रही है। इस बीच सत्ता पक्ष व विपक्ष में जमकर नोकझोंक भी हुई। ज्ञात हो कि मंगलवार को नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में नई सरकार बनी थी। विधानसभा के एक दिवसीय सत्र में सरकार बहुमत साबित करेगी। सीएम का दावा है कि उनके पास स्पष्ट बहुमत है। उधर सैनी के सीएम बनने का मामला हाईकोर्ट की दहलीज पर भी पहुंच गया है।

सीएम ने राज्यपाल को 48 विधायकों के समर्थन वाली चिट्ठी सौंपी है। सदन में रखे गए विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। स्पीकर ने सदन में 1 घंटा विपक्ष और 1 घंटा सत्तापक्ष को विश्वास मत पर बोलने का समय तय किया। उधर विधानसभा सत्र जल्दी बुलाने पर कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कोई इमरजेंसी नहीं थी। सरकार

को बहुमत सिद्ध करना है। आज करे या कुछ दिन बाद करें। इस पर स्पीकर ने कहा कि एक सदस्य के लिए हाउस स्थगित नहीं किया जा सकता।

सरकार में कुछ कमियां रही होंगी : राव दान सिंह

कांग्रेस विधायक राव दान सिंह ने कहा कि क्या इमरजेंसी थी कि अचानक विश्वास मत हासिल करने की जरूरत पड़ी। 11 मार्च को पीएम पूर्व मुख्यमंत्री की तारीफों के पुल बांधते है और रातों रात पूरा सीन बदल जाता है। मुझे लगता है कि सरकार में कुछ न कुछ कमियां जरूर रही होगी इसलिए यह कदम उठाना पड़ा। अपने बदतर हालात को छिपाने के लिए सरकार ने यह परिवर्तन किया। इधर उधर की बात मत कर यह बता कि यह कारवां क्यों लुटा।

हमें मनोहर लाल से संवेदना है : कादियान

चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक रघुबीर कादियान ने कहा कि 11 मार्च को पीएम हरियाणा आते हैं तो वहां पर पूर्व सीएम मनोहर लाल की तारीफों के पुल बांधे जाते हैं। अगले दिन यह घटना घटती है, इसका असर जनता पर भी पड़ता है। जो वोट बैंक किसी राजनीतिक पार्टी का था उसमें एन्टी इंकमबेंसी आ जाती है। मनोहर लाल के साथ हमे संवेदना है, उन्हें बड़े बेआबरू होकर बाहर निकाला गया इतना बड़ा चीरहरण तो द्रौपदी का भी नहीं हुआ था।

जजपा के पांचों विधायक बाहर निकले

सदन में पहुंचे जजपा के विधायक बाहर चले गए हैं। विश्वास मत की वोटिंग से पहले जजपा विधायक जोगीराम सिहाग, देवेंद्र बबली, रामकुमार गौतम, रामनिवास सूरजाखेड़ा, ईश्वर सिंह भी बाहर गए। निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू की सदन से बाहर निकले।

फोटो: सुमित कुमार

शपथ राजभवन में नवनियुक्त सूचना आयुक्तों को राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने शपथ दिलायी।

कैंसर की नकली दवा बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 7 गिरफ्तार

नई दिल्ली(4पीएम न्यूज़ नेटवर्क)। दिल्ली-एनसीआर में नकली दवा बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नकली दवाइयां बनाने और सप्लाई करने वाले एक अंतरराष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है, इनमें दिल्ली के कैंसर के जाने माने अस्पताल के दो कर्मचारी भी शामिल हैं। सभी आरोपी कैंसर के 1.96 लाख रुपये के इंजेक्शन में नकली दवाइयां भरकर बेचते थे। कैंसर की इन नकली दवाईयों को फार्मासिस्ट सिर्फ देश ही नहीं बल्कि चीन और अमेरिका जैसे देशों में भी सप्लाई करते थे।

पटना : सिलेंडर ब्लास्ट, महिला बच्चे समेत 14 लोग झुलसे

» घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

पटना। पटना में एक घर में भीषण आग लगी। इसमें दो रसोई गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। हादसे में में महिला, पुरुष ,बच्चे सहित 14 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए पटना की नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी का माहौल बना हुआ है।

इधर, सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि काफी देर से गैस का रिसाव हो रहा था। किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। रसोई गैस लीक होने के कारण ही इतना बड़ा हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि पटना के फतुहा थाना क्षेत्र के

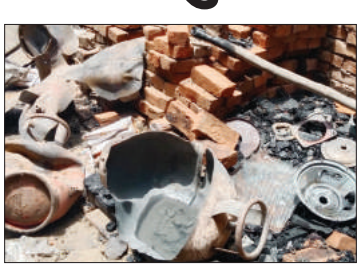

सुल्तानपुर गांव में एक घर में शादी समारोह 7 मार्च को समाप्त हुआ था। शादी समारोह के बाद घर परिवार के लोग मंगलवार की देर शाम चौथारी पूजा की तैयारी कर रहे थे। शादी समारोह में शामिल होने आए परिवार के कई लोग घर पर ही मौजूद थे। अचानक खाना बनाने के दौरान एक रसोई गैस सिलेंडर में आग लग गई। आग को देखते ही घर के लोग उसे बुझाने के लिए प्रयास शुरू कर दिया। परिवार के लोगों ने आग बुझाने के लिए कंबल और पानी का छिड़काव करने लगे।

मॉब लिंचिंग मामले में 10 आरोपियों को आजीवन कारावास

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

हापुड़। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले की एक स्थानीय अदालत ने मॉब लिंचिंग (भीड़ हिंसा) के करीब छह वर्ष पुराने एक मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

विशेष लोक अभियोजक विजय चौहान ने बताया कि अपर जिला सत्र न्यायाधीश श्वेता दीक्षित की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद भीड़ हिंसा से संबंधित मामले में 10 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 58-58 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जून 2018 में हापुड़ के धौलाना के गांव बझैड़ा निवासी कासिम (45) की गोहत?या के झूठे आरोप में भीड़ ने हत्या कर दी थी?। समयदीन (62) पर भी जानलेवा हमला किया गया था, लेकिन वह बच गया। पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर विधिक प्रक्रिया पूरी कर जेल भेज दिया था और विवेचना पूरी करने के बाद आरोपपत्र दाखिल किया।

कैफे विस्फोट का मुख्य संदिग्ध हिरासत में

» एनआईए ने बेल्लारी जिले से पकड़ा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

बेंगलुरु। आतंकवाद रोधी एजेंसी के सूत्रों ने बताया कि बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे विस्फोट मामले में एक प्रमुख संदिग्ध को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने हिरासत में ले लिया है। सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया कि शब्बीर नाम के संदिग्ध को कर्नाटक के बेल्लारी जिले से पकड़ा गया। फिलहाल संदिग्ध से पूछताछ जारी है।

आतंकवाद रोधी एजेंसी के सूत्रों ने बताया कि बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे विस्फोट मामले में एक प्रमुख संदिग्ध को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने हिरासत में ले लिया है। सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया कि शब्बीर नाम के संदिग्ध को कर्नाटक के बेल्लारी जिले से पकड़ा गया। फिलहाल संदिग्ध से पूछताछ जारी है।1 मार्च को बेंगलुरु के लोकप्रिय कैफे में कम तीव्रता वाले विस्फोट में दस लोग घायल हो गए थे। विस्फोट एक टाइमर का उपयोग करके आईईडी बम को ट्रिगर करके किया गया था। बुधवार का घटनाक्रम पुलिस द्वारा कई सीसीटीवी फुटेज जारी किए जाने के बाद आया, जिसमें मुख्य संदिग्ध दिखाई दे रहा था। 1 मार्च को, लगभग 30 साल पुराने संदिग्ध की एक तस्वीर खींची गई, जिसमें उसे कैफे के अंदर इडली की एक प्लेट ले जाते हुए दिखाया गया। उसे कंधे पर रखे बैग के साथ देखा गया, जिसके अंदर आईईडी बम होने का संदेह है। एक अन्य सीसीटीवी फुटेज में वही संदिग्ध बैग लेकर रेस्तरां की ओर जाता दिख रहा है। तीन और सीसीटीवी वीडियो का विश्लेषण करने के बाद, जांच अधिकारियों ने 9 मार्च को कहा कि कैफे विस्फोट के बाद संदिग्ध ने कई बार अपने कपड़े और रूप बदले थे। एक में वह पूरी बाजू की शर्ट और हल्के रंग की पोलो टोपी, चश्मा और चेहरे पर मास्क पहने नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरे वीडियो में वह बैंगनी रंग की आधी बाजू की टी-शर्ट और काले रंग की शर्ट पहने नजर आ रहे हैं। उसके पास अभी भी मास्क था लेकिन चश्मा नहीं था। इस बीच, तीसरे फुटेज में शख्स को न तो टोपी पहने हुए दिखाया गया और न ही चश्मा पहना हुआ। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने संदिग्ध के बारे में कोई भी जानकारी देने वाले को 10 लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा की थी, जिससे उसकी गिरफ्तारी हो सके। रामेश्वरम कैफे 8 मार्च को फिर से खुल गया।

स्वामी 4 पीएम न्यूज नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक संजय शर्मा द्वारा आस्था प्रिंटर्स, 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से मुद्रित एवं 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से प्रकाशित। संपादक - संजय शर्मा, विधि सलाहकार: सत्यप्रकाश श्रीवास्तव, मोहम्मद हैदर, वित्तीय सलाहकार: संदीप बंसल, कार्टूनिस्ट: हसन जैदी, दूरभाष: 0522- 4078371 | Email: daily4pm@gmail.com | website: www.4pm.co.in
RNI-UPHIN/2015/62233 डाक पंजी. सं- SSP/LW/NP-495/2018-2020 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद लखनऊ न्यायालय के अधीन ही होंगे।